(मंत्रालय ने योजना आयोग और संबंधित राज्य सरकारों से वानिकी के क्षेत्र के लिए आवंटनों में वृद्धि करने का भी अनुरोध किया है । राज्य सरकारों से सयुक्त वन प्रबधंन के अन्तर्गत वन संसाधनों की सुरक्षा करने और उनका विकास करने के लिए स्थानीय लोगों को प्रोत्साहित करने की भी सलाह दी गई है। वन (सरंक्षण) अधिनियम, 1980 वन भूमियों के डाइवर्जन को विनियमित करने हेतु बनाया गया है ।

केवला देव पक्षी अभ्यारण्य में प्रवासी पक्षियों की संख्या में कमी

1057. **श्री दिलीप सिंह जूदेव :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क)राजस्थान में केवला देव पक्षी अभ्यारण्य में विदेशों से आने वाले पक्षियों की संख्या में कमी आने के क्या-क्या कारण हैं;

(ख) इन पक्षियों की संख्या में प्रतिवर्ष कितने प्रतिशत की कमी आने का अनुमान लगाया है,

(ग) इस अभ्यारण्य में पिछले तीन वर्षो के दौरान पक्षियों के अवैध शिकार की कितनी घटनाएं हुई तथा उनमें से कितने व्यक्तियोंको पकड़ा गया , और

(घ) इस अभ्यारण्य में पानी की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराने, अवैध चराई तथा अतिक्रमण एवम् अवैध शिकार को रोकने के लिए की जा रही कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबूलाल मंराडी) : (क) और (ख) केवला देव राष्ट्रीय पार्क, भरतपुर केवलादेवी पक्षी अभ्यारण्य के नाम से लोकप्रिय हैं । राज्य सरकार से प्राप्त रिर्पोटों के अनुसार, विदेशों से इस पार्क में प्रवास करने वाले पक्षियों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है।

(ग) पिछले तीन वर्षो में इस पार्क में पक्षियों के अवैध शिकार संबंधी केवल एक मामले का पता चला है । तीन व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं और मामला न्यायालय में दाखिल कर दिया गया है ।

(घ) पार्क के लिए जल की पर्याप्त मात्रा प्रत्येक वर्ष राज्य सिंचाई विभाग से प्राप्त की जाती है । अतिक्रमणों और अवैध चराई को रोकने के लिए पार्क के चारों ओर पत्थर की दीवार बनाई गई है । पार्क में वायरलैस से लैस 8 पांच चौकियां स्थापित की गई है । सुरक्षा गार्डो द्वारा नियमित गश्त भी की जाती है ।

Development of Forests in Orissa

1058. SHRI BHAGABAN MAJHI: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state: (a) whether the State Government of Orissa has submitted any project/proposal to the Union Government for the development of forests in that State; *

(b) if so, the details thereof; and

(c) the steps taken to approve those projects?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI BABTJLAL MARN-DI): (a) to (c) The Government of Orissa submitted project proposals to the National Afforestation & Eco-Development Board (NAEB) under the following three schemes:—

(1) Integrated Afforestation & Eco-Development Project Scheme (IAEPS).

(2) Area Oriented fuelwood & Fodder Project Scheme (AOFFP)

(3) Non-Timber Forest Produce Scheme (NTFP).

for implementation in the IXth Plan Period. Of these, the follow* ing have been sanctioned:—

(1) AOFFP: for a total project cost of Rs. 1130.94 lakhs to treat 16,665, hectares.

(2) NTFP: for a total project cost of Rs. 492 lakhs to treat 6,000 hectares.

Three projects proposals under the IAEPS scheme for Chilka, Salandi and Tel Watersheds have been sent by the State Government on the 16th May, 1998 and are being processed.

वायु तथा जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियमों के अंतर्गत दर्ज मामले

1059. **श्री गोपाल सिंह जी** : सोलंकी, क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षो के दौरान वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा जल

0 (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1994 के अंतर्गत दर्ज किये गये मामलों की राज्य-वार संख्या कितनी-कितनी हैं;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान सरकारी तथा निजी क्षेत्र उपक्रमों फैक्ट्रियों, वाहनों, तेलशोधक कारखानों, इस्पात संयंत्रों के विरूद्ध प्रदूषण फैलाने के लिए मामले उक्त अधिनियमों के अंतर्गत दर्ज किये गये थे;

(ग) यदि हां ,तो तत्संबंधी पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है,

(घ) ऐसे मामलों की राज्य-वार संख्या कितनी-कितनी है, जिनके सदंर्भ में न्यायालयों ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पक्ष में अथवा उनके विरूद्ध निर्णय दिये हैं, और

(ड) 31 अक्तूबर, 1997 की तिथि के अनुसार विचारण हेतु लंबित पडे मामलों की संख्या कितनी है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबूलाल मंराडी) : (क) से (ड) सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

Conversion of Classified Forest Land in Andhra Pradesh

1060. SHRI YERRA NARAYANA SWAMY: Will the Minister of DENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) what is the extent of land permitted by Government to be tonverted from forest classification to non-forest classification in Andhra Pradesh in the last five years;

(b) the details of applications pending with Government from Andhra Pradesh;

(c) whether any time-bound rule for clearance is there; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI BABULAL MARANDI): (a) During last five years 3044.50 ha. of forest land had been permitted for diversion for non-forest purposes by the Ministry of Environment and Forests under Section-2 of Forest (Conservation) Act, 1980 in Andhra Pradesh.

(b) Twenty one applications are pending with this Ministry for forest clearance under Forest (Conservation! Act, 1980 from Andhra Pradesh.

(c) Yes, Sir.

(d) Under the Forest (Conservation) Act, 1980 guidelines, specific time limits have been prescribed for disposal of the proposals. As per these guidelines, the State Government should make efforts to dispose a reference at its level within a maximum period of 60 days. In respect of Central Government, these guidelines provide that cases, which are complete in all respects shall be disposed of within 90 days.

भारत एल्युमिनियम कारपोरेशन, कोरबा के विरूद्ध प्रदूषण नियंत्रण संबंधी उल्लघंन के मामले

1061. **श्री दिलीप सिंह जूदेव** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क)गत तीन वर्षो के दौरान केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा भारत एल्युमिनियम कारपोरेशन कोरबा के विरूद्ध प्रदूषण नियंत्रण के उल्लंघन के कितने मामले दर्ज किए गए;

(ख) उन मामलों का ब्यौरा क्या है जिनमें बोर्ड ने गंभीर आरोप लगाए हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान भारत एल्युमिनियम कारपोरेशन द्वारा प्रदूषण नियंत्रण हेतु किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है, और

(घ) भारत एल्युमिनियम कारपोरेशन के कार्यकरण के सबंधं में ससंदीय समिति के प्रतिनिधि मंडल द्वारा दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पिछले तीन वर्षो के दौरान भारत एल्युमिनियम कारपोरेशन, कोरबा के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) बालको ने अपने एल्युमिना, स्मैल्टर और फैब्रिकेशन संयंत्रों में आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण सुविधाएं स्थापित की है। इस उद्योग ने अपने खनन और संयंत्र क्षेत्रों में लगभग 85000 वृक्ष लगाए हैं। उद्योग ने प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय